

MSP को वैधानकि बनाने की कसिानों की मांग

प्रलिमिस के लिये:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यूनतम समरथन मूल्य, आरथकि उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य मुद्रासंकेति, प्रधानमंत्री अननदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मेन्स के लिये:

भारत में कृषि नीतियाँ, कृषि से संबंधित आरथकि चुनौतियाँ, कसिानों का वरीध, कृषि विविधीकरण एवं स्थरिता

स्रोत: लाइब्रेरी

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रदर्शनकारी कसिानों से बातचीत न करने एवं उनकी शक्तियों का समाधान न करने के लिये केंद्र सरकार की आलोचना की गई।

- न्यायालय ने केंद्र से न्यूनतम समरथन मूल्य (MSP) के लिये विधिकि गारंटी की मांग वाली नई याचिका पर जवाब देते हुए कसिानों की मांगों पर विचार करने का आग्रह किया।
- यह घटनाक्रम पंजाब-हरयाणा सीमा पर कसिान समूहों द्वारा लंबे समय से चल रहे वरीध प्रदर्शन से संबंधित है।

MSP गारंटी से संबंधित याचिका क्या है?

- याचिका: इसमें कृषि कानूनों को नरिस्त करने के बाद वर्ष 2021 के कसिान वरीध प्रदर्शन के दौरान करि गए वादों के आधार पर फसलों पर MSP हेतु विधिकि गारंटी की मांग की गई।
 - इस याचिका में मांग की गई है कि कृषि उत्पादकों के लिये स्थरि आय सुनिश्चिति करने के क्रम में MSP को विधिकि अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रत्यक्ष आदेश जारी न करते हुए, इस मुद्दे को सुलझाने के लियउच्चाधिकार प्राप्त समिति का उपयोग करने का सुझाव दिया तथा इस संदर्भ में केंद्र से तुरंत जवाब देने को कहा।
 - इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी से चल रहे वरीध प्रदर्शनों को विधिकि बल मिलने के साथ अधिकि व्यवस्थिति तथा विधिकि समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

भारत में कसिानों के वरीध प्रदर्शन का क्या कारण है?

- कसिानों के वरीध प्रदर्शन का कारण: यह वरीध प्रदर्शन भारत के वर्ष 1991 के आरथकि उदारीकरण से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शक्तियों से प्रेरित है, जिसमें कृषि की तुलना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ कसिान कम फसल लाभ एवं बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं) में संकट बढ़ रहा है।
 - यद्यपि सरकार कई फसलों के लिये MSP नरिधारति करती है लेकिन इसका क्रियान्वयन सीमित है तथा इसके तहत खरीद ज्यादातर चावल एवं गेहूँ की ही होती है।
 - कसिान (विशेषकर गैर-प्रमुख फसल क्षेत्रों के संदर्भ में) अक्सर उत्पादन लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं।
 - विश्व व्यापार संगठन (WTO) के समझौते (जिन्हें प्रायः मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाले समझौतों के रूप में देखा जाता है), व्यापार प्रतिविधि लगाने या कसिानों को सबसेडि प्रदान करने की भारत की क्षमता को सीमित करते हैं।
 - प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इससे कसिानों के लिये खरीद नीतियों एवं सबसेडि को नियंत्रित करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।

- कसिनों की प्रमुख मांगें: प्राथमिक मांग एक ऐसे कानून की है जो सभी फसलों के लिये MSP की गारंटी देता है।
 - यह **सवामीनाथन आयोग की रपोर्ट** पर आधारित है, जिसमें 'C2+50%' फारमूले का उपयोग करते हुए उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जनी की सफिरशी की गई है।
 - व्यापक लागत (C2) में सभी भुगतान कर्ति गए व्यय, अवैतनिक पारविरकि श्रम का अनुमानित मूल्य, करिया, तथा स्वामतिव वाली भूमि और स्थायी पूँजी पर छोड़ा गया ब्याज शामिल है।
 - जबकि **MSP वर्तमान में A2+FL से 50% अधिक निरिधारित है**, जिसमें भुगतान कर्ति गए व्यय और अवैतनिक पारविरकि श्रम शामिल हैं।
 - अन्य प्रमुख मांगें: कसिनों और मजदूरों के लिये पूरण ऋण माफी। कसिनों के लिये मुआवजा और पेंशन, विशेष रूप से वरिध प्रदर्शन या कृषि संकट से प्रभावित कसिनों के लिये।
 - कृषि श्रमिकों के लिये बेहतर कार्य स्थितियाँ और मजदूरी।
 - भूमि और जल पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों का संरक्षण।
- सरकार का दृष्टिकोण: केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि **MSP** के लिये कानूनी गारंटी देना अव्यवहारिक होगा, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और खरीद की उच्च लागत शामिल है।
 - सरकार ऐसी नीति के आर्थिक प्रभावों को लेकर भी चिंतित है, जिसमें **खाद्य मुद्रासंफीति** और बजटीय बाधाएँ शामिल हैं।

MSP के वैधता के पक्ष और विपक्ष में तरक्क क्या हैं?

- **MSP के वैधता के पक्ष में तरक्क:**
 - **कसिनों की प्रेशानी का समाधान:** MSP को वैध बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि कसिनों को उनकी फसलों के लिये उचित मूल्य मिले, बाजार में उत्तर-चढ़ाव से होने वाले कम लाभ की समस्या दूर होगी तथा उत्पादन लागत को कवर करके और कसिनों के लिये उचित लाभ की गारंटी देकर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
 - भारत की अरथव्यवस्था में कृषि का हस्सा 15% से नीचे गिर गया है, तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद कसिनों की आय में न्यूनतम वृद्धि हुई है।
 - MSP को वैधानिक बनाने से उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषिविकास को समर्थन देकर इस अंतर को कम किया जा सकता है।
 - **औपचारिक बाजारों को बढ़ावा देना:** MSP को वैध बनाने से औपचारिक बाजार लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, अनौपचारिक बाजारों पर निरिधारण कम होगी, तथा **डिजिटल कृषि** के माध्यम से प्रारब्धिता बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य के साथ तालिमेल हो सकेगा।
 - **स्थिर बाजार मूल्य:** MSP को वैध बनाने से कृषि बाजार में मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है, जिससे कृषि आय और उपभोक्ता मूल्य दोनों स्थिर हो सकते हैं।
 - **लागत गणना विधियाँ:** लागत गणना की वर्तमान विधियाँ प्रायः कृषि की वास्तविक लागत को दर्शाने में वफिल रहती हैं, जिसके परणिमासवरूप कीमतें कसिनों के व्यय से भी कम हो जाती हैं।
 - अधिक स्टीक मूल्य निरिधारण मॉडल, जैसे कि C2+50% पद्धति, कृषि मूल्यों को अन्य क्षेत्रों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित कर सकती है।
 - **कृषि निवेश:** MSP को वैध बनाने से कसिनों को पूर्वानुमानित आय प्राप्त होगी, कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सतत पद्धतियों और हरति प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पादकता में सुधार होगा।
- **MSP के वैधता के विपक्ष तरक्क:**
 - **तारककि चुनौतियाँ:** देश भर में सभी फसलों पर MSP लागू करना अप्रयाप्त बुनियादी ढाँचे के कारण कठनी है, जैसे किमंडी प्रणाली, जो कई राज्यों में करियाशील नहीं है।
 - **सरकार के लिये उच्च लागत:** सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिये अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे बजटीय बाधाएँ और संभावित आर्थिक तनाव बढ़ेगा।
 - **खाद्य मुद्रासंफीति:** MSP के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे, विशेषकर यदिसरकार को सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिये बाध्य किया जाए।
 - **बाजार में बाधाएँ:** MSP का सांवधिकरण कृषि बाजारों में आपूर्ति और मांग की वर्तमान गतिशीलता को बाधित कर सकता है, जिससे अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
 - **विशेष व्यापार संगठन की बाधाएँ:** विशेष व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते सरकार की सबसेडी प्रदान करने या कृषि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की क्षमता को सीमित करते हैं, जिससे MSP के सांवधिकरण की प्रभावशीलता कमज़ोर हो सकती है।

देश भर में MSP को वैध बनाने के विकल्प क्या हो सकते हैं?

- **लक्षित दृष्टिकोण:** फसलों के एक छोटे प्रतिशत के लिये MSP के सांवधिकरण से खरीद प्रणाली को प्रभावित किया बना कीमतों को स्थिर किया जा सकता है।
 - इसे प्रधानमंत्री अनन्दाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो MSP और मूल्य न्यूनता भुगतान के माध्यम से कसिनों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
 - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने खरीद प्रणालियों का सफलतापूर्वक विस्तार किया है।
 - क्षेत्रीय कृषि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये, राष्ट्रव्यापी स्तर पर MSP को वैध बनाने के बजाय स्थानीय प्रसिद्धियों के अनुरूप राज्य-विधिएँ कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है।
- **सहकारिता की भूमिका:** एक विकल्प के रूप में सहकारी समतियों और FPO को बढ़ावा देना, जो दूध उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों में सफल रहे हैं।

- **सहायक बुनियादी ढाँचा:** सहकारी समतियों और FPO के लिये एक मज़बूत कानूनी ढाँचा, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ एवं बेहतर बुनियादी ढाँचा आवश्यक है।
 - प्रधानमंत्री कसिन सम्पदा योजना (**PMKSY**) बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर तथा फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान को कम करके इसकी पूरता किए सकती है।
- **अनुबंध खेती:** कसिनों और नगिमों या सहकारी समतियों के बीच अनुबंधों को प्रोत्साहित करना, जहाँ कसिन अपनी उपज के लिये गारंटीकृत मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
- **फसल बीमा योजनाएँ:** **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** जैसी पहलों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं या बाज़ार में उत्तार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से कसिनों को बचाने के लिये फसल बीमा का वसितार और सुधार करना।
- **विविधीकरण:** कसिनों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधिता लाने के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे कुछ फसलों पर उनकी नियन्त्रण कम हो सके, जिससे बाज़ार में अस्थिरिता आती हो।



MINIMUM SUPPORT PRICE (MSP)

The rate at which the govt. purchases crops from farmers; based on a calculation of at least 1.5x the cost of production incurred by the farmers

RECOMMENDED BY

Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) (recommends MSPs for 22 mandated crops and Fair and Remunerative Price for Sugarcane) Drishti IAS

22 MANDATED CROPS

Drishti IAS (14 Kharif, 6 Rabi and 2 Other Commercial crops) AS

- 7 CEREALS** Paddy, Wheat, Barley, Jowar, Bajra, Maize And Ragi
 - 5 PULSES** Gram, Arhar/tur, Moong, Urad And Lentil
 - 7 OILSEEDS** Groundnut, Rapeseed/mustard, Soyabean, Sunflower, Sesamum, Safflower And Niger Seed

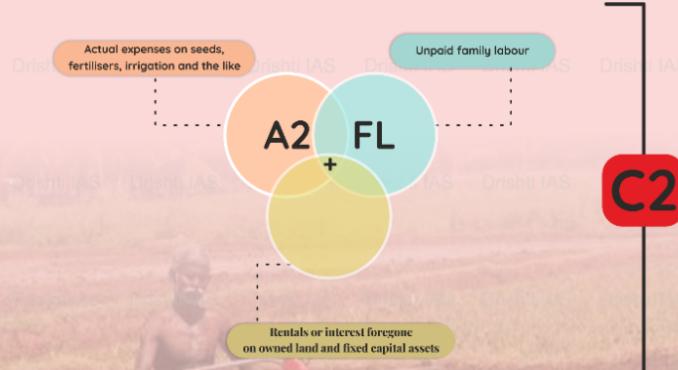
RAW COTTON **RAW JUTE** **COPRA**

MSP is the price at which the govt. is supposed to procure the mandated crops from farmers if the market price falls below it

FACTORS FOR RECOMMENDING MSP

- Cost of cultivation
 - Demand-Supply situation for the crop
 - Market price trends
 - Inter-crop price parity Drishti IAS Drishti IAS Drishti IAS Drishti IAS
 - Implications for consumers (inflation)
 - Environment (soil and water use)
 - Terms of trade b/w agri and non-agri sectors (ratio of farm inputs and outputs)

Considers both A2+FL and C2 costs



MSP has no statutory backing — a farmer cannot demand MSP as a matter of right



Drishti IAS

प्रश्न:

प्रश्न: भारत में सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने के नहितारथों पर चरचा कीजिये। क्या इसे कृषि संकट को दूर करने का एक स्थायी समाधान माना जाना चाहयि?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों एवं तलिहनों का 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्राप्ति (खरीद) भारत के कसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यू.टी.) में अस्तीमति होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP कसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जसि स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न:

प्रश्न. खाद्यानन् वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/farmer-s-demand-for-legalizing-msp>